भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 56
(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

दिवालिया कंपनियां

56. श्री एम. बदरुद्दीन अजमलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कंपनियां दिवालिया हो गई हैं जिससे हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही देश के बैंकों को लाखों का नुकसान हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी कंपनियों से बैंकों को होने वाले भारी नुकसान से बचाने की कोई योजना है क्योंकि कई रिपोर्टों से पता चलता है कि विभिन्न कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत नियामक, ऐसी सूचना नहीं रखता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सितंबर 2023 के अंत तक 7058 कंपनियों को सीआईआरपी में शामिल किया गया है। उनमें से 5057 मामलों में प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 808 को समाधान योजनाओं द्वारा बंद कर दिया गया है; 2000 मामलों को वापस

लेने/अपील/समीक्षा/निपटान के रूप में निपटाया गया है और 2249 मामलों को परिसमापन प्रक्रिया शुरू करके निपटाया गया है। कुल 2001 प्रक्रियाएं चल रही हैं।

****